भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.-2358
उत्तर देने की तारीख-15.12.2025

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वित्तीय कमी

†2358. **श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के अंतर्गत उन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/अन्य विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने विगत दस वर्षों के दौरान वित्तीय घाटे की सूचना दी है और प्रत्येक मामले में घाटे की मात्रा कितनी है;
(ख) क्या इस प्रकार के घाटे से वेतन, अवसंरचना विकास, छात्र कल्याण और अनुसंधान कार्यकलापों पर प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों को समय पर अनुदान प्रदान करना सुनिश्चित करने और छात्रों की फीस पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए मौजूदा वित्तपोषण तंत्र की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने और दीर्घकालिक स्थायित्व प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
(ङ) देश में उच्च शिक्षा के लिए जीडीपी का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित स्वायत्त संस्थान हैं और वे उसके तहत बनाए गए अपने स्वयं के अधिनियमों, संविधियों, अध्यादेशों और विनियमों आदि द्वारा अभिशासित होते हैं तथा वे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों में निर्णय लेने में सक्षम हैं। शिक्षा मंत्रालय "केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान" के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को ब्लॉक अनुदान जारी करता है, जो बदले में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को उनकी यथार्थवादी आवश्यकताओं, विगत वर्ष के दौरान किए गए व्यय के साथ-साथ निधियों की उपलब्धता के आधार पर निधियां आवंटित करता है। यूजीसी द्वारा यथासूचित, विगत दस वर्षों के दौरान, 47 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का अनुदान 5621.38 करोड़ रुपये (वर्ष 2015-16 में) से बढ़ाकर 12776.77 करोड़ रुपये (वर्ष 2024-25 में) कर दिया गया है।

(ङ): शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट "शिक्षा संबंधी बजटीय व्यय वर्ष 2019-20 से 2021-22 का विश्लेषण" के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में शिक्षा संबंधी कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 4.12% था, जिसमें से 1.29% उच्चतर शिक्षा पर व्यय किया गया।

*****